प्रस्तावों के लिए 260 अनुमोदित शामिल हैं जिनमें 588.63 करोड़ रु० की विदेशी/एन०आर०आई० इक्विटी अन्तर्ग्रस्त है । आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना एक अनवरत प्रक्रिया है और जब आवश्यक होता है, ये परिवर्तन किए जाते हैं ।

कानपुर के चमड़ा उद्योग में संकट की स्थिति

1296. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में चमड़ा उद्योग, सहायक फैक्ट्रियों के बंद हो जाने के कारण संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1297 *[Transferred to the 17th March, 1992]*

Recession in two-wheeler industry

1298. SHRI P. UPENDRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a serious recession in the two-wheeler industry; and the production has further dropped during the last quarter of 1991; and

(b) if so, the reasons therefor and what assistance Government propose to provide to the two-wheeler industry to regain its viability?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P.J. KURIEN) : (a) There is a decline in the production of two wheelers in the country during the period October-December 1991, as compared to the corresponding period of last year.

(b) This could be attributed to decline in demand resulting from tightening of monetary policy of Government in order to control fixed deficit and increase in prices. Government has since relaxed the import compression measures.

उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों की स्थापना

1299. **श्री ईशदत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान और आठवीं पचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में मझौले और बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कुल कितना निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में ग्रामीण लघु उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी धन राशि प्रदान किए जाने की सभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) 8वीं पचवर्षीय योजना अवधि (1992–97) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में बड़े, मझौले और लघु उद्योग लगाने के लिए अनुमोदित परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, चालू वर्ष (1991–92) के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना में योजना आयोग ने बड़े तथा मझौले उद्योगों के लिए 6450 लाख रुपये और ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए 4436 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है ।